USA, which is working under the UN Charter, to develop an inexpensive type of vaccine. I wonder what the Government has done in this regard! Are you following it up with these people to develop the vaccine on a war footing basis, as it is an epidemic that is spreading like wildfire?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, पहले तो मैं यह बता दूं—क्योंकि उनके सवाल के दो भाग हैं—जहां तक आकड़ों का सवाल है, स्वयं यू एन ऐड्स के पीटर पी औट यहां आए थे और उन्होंने हमारे आंकड़ों पर सहमति दी है। जहां तक आयाबी का सवाल है, कपिल सिब्बल जी यहां बैठे हैं जो इंडियन एड्ए वैक्सीन इनीशिएटव से जुड़े हुए हैं और मुझे सदन को आपके मार्फत बताते हुए खुशी हो रही है कि आयाबी ने आईसीएमआर के साथ जो एमओयू साइन किया है, हम एड्स वेक्सीन बनाने के कगार पर हैं। जो डेवलप किया है, उसके प्री क्लीनिकल ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं और शायद हिन्दुस्तान पहला देश होगा, जो एड्स वेक्सीन बनाकर देगा। हम लोग पहले होंगे जो एड्स वेक्सीन डेवलप करेंगे।

Anti-India propaganda by BBC

*183 SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the TV programme, "Question Time India", telecast over BBC on Friday August 22, 2003 night relating to Kashmir;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) what is Government's control and regulation on media agencies to prevent anti-Indian propaganda and to ensure that they confirm to publicity norms and principles keeping in mind the policies of integration and the Constitution of India?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The contents of the TV programme titled "Question Time India" telecast over BBC on Friday, August, 22, 2003 relating to Kashmir

have been noted. This was a panel discussion commissioned by BBC with the panellists including Shri Mufti Mohammad Sayeed, Chief Minister of J&K, Shri Omar Abdullah, MP, Professor Amitabh Matto, Vice Chancellor, Jammu University, Dr. Nirmal Singh, a BJP leader and Sajjad Lone of the Hurriyat Group. The programme was uplinked from Singapore.

(c) All TV Programmes, transmitted/retransmitted through the cable service, have to be in conformity with the prescribed Programme Code. The Programme Code, *inter-alia*, prescribes that no programme should be carried in the cable service, which is likely to encourage or incite violence or contains anything against the mantenance of law and order or which promote anti-national attitudes and also those programmes, which contain anything affecting the integrity of the nation. An officer authorised to implement the Act within his local jurisdiction can, by order, prohibit any cable operator from transmitting or re-transmitting any programme or channel if it is not in comformity with the Programme Code, if he/she think it necessary or expedient so to do in public interest.

श्री कलराज मिश्र: सभापति जी, जो मैंने मूल प्रश्न दिया था वह इस प्रश्न पत्र में छपा नहीं है। मेरा मूल प्रश्न था, Whether Government's attention was drawn to the NDTV Programme "Question Time India" telecast over BBC on Friday, August 22, 2003 night to impress on public mind and to project that there was

(i) a Kashmir problem
(ii) It was not created by Pakistan but by India; and
(iii) that plebiscite and independence were the only solution.

If so, the Government's reaction thereto.

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न भेजा था, वह प्रश्न इसमें नहीं छपा है।

श्री सभापति: चलिए जवाब दे दीजिए।

श्री कलराज मिश्र: जो इस प्रश्न का जवाब आया है वह तो ठीक है।

श्री सभापति: आपने जो सवाल किया है ये उसका जवाब दे देंगे, दे देंगे ना?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, कश्मीर के संबंध में हमारी यह कोशिश रही है कि टेलीविजन, रेडिया के माध्यम से भी चर्चा हो ताकि लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। लेकिन ऐसा करते समय हमारा जो प्रोग्राम कोड है केबल एक्ट के अंतर्गत, उसमें एंटी इंडिया

फीलिंग्स नहीं आ सकती या भारत को तोड़ने वाली कार्यवाहियों का समर्थन नहीं हो सकता, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। माननीय सदस्य श्री कलराज मिश्र जी ने जिस कार्यक्रम की चर्चा की है उस कार्यक्रम की टेप को मैंने स्वयं बनाया है और स्वयं देखा भी है। वहां पर उस कार्यक्रम में हर पार्टी के पॉलिटीकल लीडर उपस्थित थे। श्रीनगर में यह कार्यक्रम हुआ था। वहां पर चर्चा तो अच्छी हुई थी। कश्मीर के मामले में चर्चा खुलकर हुई थी। एक दो संदर्भ ऐसे आए थे जिसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता थी और हमने विशेष रूप से चैनल के लोगों को विभाग की ओर से बताया है कि जब आप ऐसे कार्यक्रम करें तो प्रोग्राम कोड की जो आवश्यक अहर्ताएं हैं उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: सभापति महोदय, जहां राष्ट्रीय हितों का ऐसा प्रश्न होता है वहां एक ऐसी प्रक्रिया के निर्माण करने की आवश्यकता है कि जहां हमारा व्यू प्वाइंट, हमारा दृष्टिकोण कहा जा सके। क्या इस प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कोई पहल की जा रही है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, जैसाकि मैंने आरंभ में बताया है कि हमारे केबल एक्ट के अंतर्गत एक प्रोग्राम कोड है जहां पर विधि निषेध सारे तत्वों का पूरा प्रावधान है। इसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी कार्यक्रम बनाते समय हिंसा को प्रोत्साहन, भारत की एकता को तोड़ने और भारत की अखंडता को रोकने जैसी कार्यवाहियों का प्रोत्साहन नहीं हो सकता। महोदय, माननीय सदस्य सिंघवी साहब ने जो बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस प्रोग्राम में जब यह चर्चा हुई थी तो वहां एक पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि इस चर्चा में जो लोग शामिल हैं वे शायद पूरे जम्मू-कश्मीर के मानस का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह बात भी आई है लेकिन भारत सरकार की ओर से हम चाहते हैं कि इन माध्यमों का जम्मू-कश्मीर में सदुपयोग हो ताकि एकाग्रता को हम प्रोत्साहित कर सकें।

श्री बालकवि बैरागी: सभापति महोदय, मैंने समय-समय पर सूचना मंत्री जी का ध्यान कई बार इस ओर आकर्षित किया है और मैं आज फिर सदन के माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि बौद्धिक स्तर पर चाहे बीबीसी हो या रेडिया पाकिस्तान हो या पाकिस्तान का टेलीविजन हो, यह बराबर हमारे खिलाफ एक अभियान चला रहा है। लेकिन उसका सामना करने के लिए उस फ्रंट पर हमारे पास सूचना विभाग के अंतर्गत जितने पद हैं वे खाली पड़े हुए हैं और वहां पर वे लोग रहते भी नहीं हैं। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि जब आपसे निवेदन किया है। मैं पुन: आपसे उनकी नियुक्तियों के बारे में और पद स्थापना के बारे में प्रार्थना करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि वहां के रिक्त स्थान कब तक भर दिए जाएंगे ताकि हम वहां लोगों को बुलाकर पूरी बातचीत कर सकें। आप स्वयं इस बात से अवगत हैं कि अभी लोग जम्मू में रहकर श्रीनगर के पदों पर जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। वे वहां रहते ही नहीं हैं। वहां सारे पद खाली पड़े हुए हैं तो आप कब तक उनको पूरा कर देंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, माननीय सदस्य श्री बालकवि बैरागी जी के प्रश्न के दो स्वरूप हैं एक तो पदों की रिक्तियों के भरने के संबंध में है और दूसरा कार्यक्रमों के बारे में है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हम पीटीवी के झूठ वगैरह को खोलने के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। एक कार्यक्रम 'पीटीवी का सच' है जो दूरदर्शन पर आता है। यह काफी लोकप्रिय प्रोग्राम है और दूसरा प्रोग्राम 'पाकिस्तानी रिपोर्टर' है। यह भी काफी लोकप्रिय प्रोग्राम है। जहां तक पदों की रिक्ति के बारे में है, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कश्मीर की, विशेषकर श्रीनगर की स्थिति से सदन अवगत है। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहुंगा कि वहां पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के पदाधिकारयों ने मिलिटेंट्स के तमाम दवाब और थ्रेट को सहते हुए कार्यक्रम को चलाने की कोशिश की है। यह बहुत गर्व की बात है और मैं इसके लिए उनकी हृदय से बहुत सराहना करना चाहता हूं। कुछ पद खाली जरूर हैं, पदों को भरने के संबंध में कठिनाइयां आती हैं। हम सब वहां की परिस्थितियों से परिचित हैं, थोड़ा व्यापक विस्तार करना पड़ेगा। बैरागी जी ने मुझे इन चिंताओं को बताया है, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी-जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

Incentives for units in SEZ

184. SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to extend additional incentives for setting up of units in the Special Economic Zones through a five year exemption from Provident Fund/Employees State Insurance liabilities for the entrepreneurs;

(b) whether it is also proposed to relax labour laws and trade union Acts to attain higher and committed productivity;and

(c) whether Government expect that these incentives would spur growth of the existing SEZs and also the new ones coming up especially in Padubidri in Dakshina Kannada region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE): (a) to (c) A Statement is laid on theTable of the House.

Statement

(a) The Special Economic Zones (SEZs) scheme aims to provide an internationally competitive duty free environment for export production